

भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
स्व० जगन्नाथराव जोशी सभागार
(बेंगलूरु—कर्नाटक)
(12-14 सितम्बर - 2008)

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता
श्री लालकृष्ण आडवाणी का समापन भाषण

श्री राजनाथ सिंहजी, श्री जसवंत सिंह जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण,

मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, बिहार में हाल में आई अभूतपूर्व बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह बाढ़ से उत्पन्न कोई साधारण त्रासदी नहीं है जिसे दुर्भाग्यवश बिहार की जनता लगभग हर साल झेलती आ रही है। यह वास्तव में सुनामी के समान एक राष्ट्रीय आपदा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी और बिहार में जे.डी.यू.—भाजपा सरकार में उनके सहयोगीगण इस आपदा का मुकाबला करने के लिए तुरन्त जुट गए। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा की गंभीरता और इसके कारणों के स्वरूप को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए।

जिस तरह से बिहार, असम और देश के अन्यो हिस्सों के लोग लगभग हर वर्ष बाढ़ों से प्रभावित होते हैं वे न केवल राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण जैसे सामान्य कार्यों की ही अपेक्षा करते हैं बल्कि वे बाढ़ों की रोकथाम की एक प्रभावी नीति बनाए जाने की भी जरूरत महसूस करते हैं। यदि जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए.) को नई दिल्ली में अगली सरकार बनाने के लिए जनादेश देती है तो हम बाढ़ नियंत्रण के लिए तत्काल एक व्यापक तथा दीर्घकालीन नीति बनाने का कार्य शुरू करेंगे। जहां कहीं संभव होगा, हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की महत्वाकांक्षी **नदी जोड़ो परियोजना** जिसे यू.पी.ए. सरकार ने निर्दयतापूर्वक छोड़ दिया है, को पुनर्जीवित करके बाढ़ रोकथाम तथा सूखा रोकथाम की नीतियों को भी समन्वित करेंगे।

यू.पी.ए. सरकार को जाना होगा, नए चुनावों के लिए आह्वान

कल शाम दिल्ली में हुए श्रृंखलाबद्ध बम—विस्फोटों में मारे गए लोगों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यू.पी.ए. सरकार के शासनकाल में आतंकवादियों को कोई डर नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और यू.पी.ए. सरकार स्वयं इस डर से ग्रसित है कि जब वह आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाएगी तो उसे

वोट बैंक से हाथ धोने पड़ेंगे। आतंकवाद तथा अलगाववाद से लड़ने में सरकार की अनिच्छा और अक्षमता ने भारत की एकता और सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व खतरा पैदा कर दिया है। साथ ही, सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने में यू.पी.ए. सरकार की विफलता से आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है।

संक्षेप में, यू.पी.ए. सरकार देश और आम आदमी के लिए एक अभिशाप बन गई है। सरकार की महाविफलता (मूल्यवृद्धि तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में), महाकांड (हाल में हुआ 'वोटों के लिए पैसा' कांड जो भारतीय संसद के प्रति एक अपराध था) और महाधोखा (भारत-अमेरिका के बीच परमाणु समझौता जिसके बारे में हाल में रहस्योद्घाटन हुए हैं) :

1. संसद को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन; और
2. देश में प्रत्येक घर को बिजली पहुंचाने का बहाना बनाकर समझौते में जनता से धोखा।

मनमोहन सिंह की रीढ़विहिन सरकार ने एक भी दिन सत्ता में बने रहने की हर वैद्यता खो दी है। इसे नए संसदीय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करते हुए तत्काल सत्ता छोड़ देनी चाहिए ताकि जनता नई सरकार चुन सके जिसमें राष्ट्र के समक्ष गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़-निश्चय और क्षमता हो।

12 सितम्बर और बंगलौर का मेरे जीवन में महत्व

मेरे प्रिय सहयोगियो, इस बैठक के लिए बंगलौर का चयन और बैठक की शुरुआत के लिए 12 सितम्बर का फैसला, मुझे स्मृतियों में ले गया है। 12 सितम्बर मेरे जीवन का कभी न भूलने वाला दिन है। यह वह दिन है जब 1947 में मैं अपने जन्मस्थान करांची, जहां मैंने अपनी जीवन के बीस वर्ष बिताए को छोड़कर विभाजन के बाद भारत आया। मुझे उन घटनाओं का स्मरण आ रहा है जो मेरे यहां आने से पहले घटीं।

मैं 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हुआ था। विभाजन से दस दिन पूर्व 5 अगस्त, 1947 को सिंध में हिन्दुओं की सर्वाधिक बड़ी रैली हुई थी। संघ की कराची शाखा का सचिव होने के नाते मुझे इस रैली को संगठित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस रैली में परम पूजनीय श्री गुरुजी (श्री एम.एस. गोलवलकर) की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया था और जिनके उद्बोधन ने सिंधी हिन्दुओं, जो कांग्रेस के चलते अपने को पूर्णतया ठगा हुआ और निराश्रित महसूस कर रहे थे, के मनो में आशा और हिम्मत बंधाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा सक्रिय संबंध राजस्थान में भी बना रहा। भारतीय जनसंघ की 1951 में स्थापना के बाद से मैं इसका पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बना। मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के साथ निकट से काम

करने का सौभाग्य मिला। उनके व्यक्तित्व जो आदर्शवाद, सिद्धांत तथा व्यावहारिक समझदारी का सम्मिश्रण था, ने मेरे राजनीतिक व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव डाला।

यदि करांची से निर्वासन और बाद में जनसंघ में शामिल होना मेरे शुरूआती जीवन में निर्णायक मोड़ थे तो 26 जून, 1975 अगला मोड़ था जब आपातस्थिति घोषित होने की सुबह ही अटलजी के साथ मुझे भी बंगलौर में गिरफ्तार किया गया। अगले 19 महीनों तक अधिकतर बंगलौर सेंट्रल जेल ही मेरा निवास बना।

मैंने अपने व्यक्तिगत अतीत का थोड़ा बहुत इसलिए उल्लेख किया क्योंकि जब मैंने अपने जीवन के अतीत को देखता हूँ और विशेषकर बाद के निर्णायक मोड़ों (1980 में भाजपा का गठन, 1990 में अयोध्या आन्दोलन के दौरान रामरथ यात्रा, स्वराज को सुराज में बदलने पर जोर देने हेतु 1997 में 59 दिनों की स्वर्ण-जयंती रथ यात्रा, 1998 में अटलजी के प्रधानमंत्रित्व में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का गठन), से मैं संतुष्टि अनुभव करता हूँ कि पार्टी की वृद्धि में मेरा भी थोड़ा-बहुत योगदान रहा है। इस लम्बी यात्रा में अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले सहयोग और विश्वास के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ। हम सब मिलकर इस तथ्य पर गर्व कर सकते हैं कि भारत की राजनीति में हमने कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को समाप्त कर इसे मुख्य रूप से द्विध्रुवीय बना दिया है। हम निम्न तथ्यों पर भी गर्व कर सकते हैं जिन पर हम हमेशा अडिग रहे हैं—

- भारत की एकता की रक्षा के लिए (डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया);
- भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए (जब जनसंघ के लाखों कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के विरुद्ध लड़ते हुए यातनाएं सही)
- सेक्युलरिज्म के सही अर्थ को स्थापित करने के लिए (जब हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आंदोलन में शामिल हुई)
- सुशासन, विकास और सुरक्षा के आदर्शों को प्रोत्साहित करने के लिए (उदाहरण — वाजपेयी सरकार के 6 वर्ष और गुजरात की वर्तमान श्री नरेन्द्र मोदी सरकार)।

हालांकि हमारी पार्टी कभी अतीतगामी नहीं रही। हम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से परिचित हैं। इतिहास ने हम पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम इससे परिचित हैं और हम इसे कभी भी नजरों से ओझल नहीं होने देंगे।

कर्नाटक : दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवेश द्वार

मित्रो, हम यहां बंगलुरु में भारत के राजनीतिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर एकत्रित हुए हैं। चौदहवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही यू.पी.ए. सरकार का दागी कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाये गये आपातकाल को छोड़कर, ऐसा कभी नहीं

हुआ कि किसी सत्तारूढ़ सरकार ने ऐसे अनेक कारण दिए जिससे जनता ने उसे सत्ता से बाहर किया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सहयोगी दलों को बदलाव चाहने वाली जनता को सत्ता-परिवर्तन कराने का एक मौका और वास्तव में, जिम्मेदारी मिली है। **हमें उनकी आकांक्षा को पूरा करना होगा।**

इसी कारण से इस बैठक के लिए बंगलुरु का चयन करना बहुत ही उपयुक्त रहा। कई साल पहले हमने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक शासक दल बनाने का संकल्प लिया था। कर्नाटक के हमारे साथियों ने इस वर्ष जून में हुए विधानसभा चुनावों में इस संकल्प को वास्तविकता में बदल दिया है। मैं श्री बी.एस. येदियुरप्पाजी के दृढ़निश्चयी और लोकप्रिय नेतृत्व के लिए उनकी सराहना करता हूँ। पिछले सप्ताह उन्होंने अपने कार्यकाल के कार्य-निष्पादन के सौ दिन पूरे किए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकास की इस गति को बनाए रखा जाए और जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाए। साथ ही, ऐसे गलत कदम उठाने से बचा जाए जिनसे कर्नाटक की पिछली सरकारों को नुकसान पहुंचा और विघटन हुआ।

सफलता से हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कर्नाटक तथा भाजपा-शासित दूसरे राज्य भी सरकार तथा पार्टी के बीच सही समन्वय बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करे ताकि हमारे पार्टी कार्यकर्ता-वास्तव में, निर्वाचन क्षेत्र के सैद्धांतिक मित्रभाव रखने वाले हमारे सभी शुभचिंतक और समर्थक यह महसूस करें कि यह उनकी सरकार है तथा उनका यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि सरकार के कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों की जनता को प्रभावी ढंग से जानकारी मिले। हमने पहले, विशेषकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के समय जो गलतियां की थीं, वे अब न दोहराई जाएं।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में विजय की ओर

मित्रो, दक्षिण भारत में अपनी पहली सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार में इसकी पहली सफलताओं से यह अनुमान लग गया है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में 2004 के बाद से किस तरह से जबरदस्त बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी ने एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में सत्ता गंवाई है। अब इस पार्टी के लिए केन्द्र में सत्ता से हटने का समय आ गया है।

केन्द्र में कांग्रेस को खदेड़ने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पहले उन राज्यों में पराजय का स्वाद चखे जहां इस वर्ष नवम्बर में नई विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उनमें से तीन राज्यों—**राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़** में हमारी सरकारें हैं। **दिल्ली** दूसरा राज्य है जहां इसी समय नई विधानसभा के लिए चुनाव होंगे।

हम सभी इन चुनावी लड़ाइयों के महत्व को भलीभांति जानते हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नया जनादेश हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। इसका श्रेय उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों—सुश्री वसुन्धरा राजे, श्री शिवराज सिंह चौहान और डा० रमन सिंह के अच्छे कामकाज को जाता है। हमारे पास दिल्ली में सत्ता में लौटने के लिए भी मौका है। जहां कांग्रेस के दस साल के शासनकाल ने लोगों के मन में एक ऐसी तीव्र इच्छा जगा दी है कि वे भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में देखना चाहते हैं।

फिर भी, मैं इन चार राज्यों के अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि वे चुनाव की तैयारी के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर न छोड़ें तथा चुनाव से सम्बन्धित किसी भी कार्य की अनदेखी न करें। इस सन्दर्भ में दो बातें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। पहली, हमें कुछ विधानसभाओं में स्थानीय स्तर की **Anti-incumbency** के प्रति सतर्क रहना होगा। उम्मीदवार का चयन करते समय इस तथ्य को नुक्सान पहुंचाने वाली संभाव्यता की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। दूसरी, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, की सर्वोच्चता (**Supremacy**) को भी बनाए रखना चाहिए। मतदाता पार्टी के भीतर कोई भी कलह नहीं देखना चाहते हैं।

एक मांग उठ रही है कि **जम्मू व कश्मीर** में विधानसभा चुनावों को स्थगित किया जाए। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा करने से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को एक गलत संदेश जाएगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव इस वर्ष की समाप्ति से पहले कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने का हमें संकल्प लेना चाहिए।

यू.पी.ए. सरकार का आम आदमी और किसान के साथ धोखा

मित्रो, हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने गर्व से यह दावा किया है कि यू.पी.ए. सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जनता से जो वायदे किए थे उन सभी को पूरा कर दिया है। वे या तो अपनी बनाई ख्याली दुनिया में जी रहे हैं या वे समझते हैं कि जनता बेवकूफ है जो आसानी से उन पर विश्वास कर लेगी। सरकार के बारे में कोई भी यह बता सकता है कि वह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को काबू करने में अपनी विफलता के कारण गरीब तथा मध्यम श्रेणी के परिवारों की बदहाली को बढ़ाने में गर्व महसूस कर रही है। **जहां तक आम आदमी का सम्बन्ध है, अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि का भार ही यू.पी.ए. सरकार को सत्ता से बाहर करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बनेगा।**

मुद्रास्फीति को रोकने में यू.पी.ए. सरकार की विफलता की भारी कीमत चुका रही है। आर्थिक वृद्धि दर धीमी चल रही है। इसके परिणामस्वरूप, हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। एन.डी.ए. सरकार द्वारा मध्यम श्रेणी के लिए शुरू की गई आवास नीतियों के कार्यान्वयन में अब ठहराव आ गया है। बढ़ती हुई ब्याज दरों से अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर छोटे तथा मझोले व्यवसाय आहत

हो रहे हैं। मध्यम श्रेणी के परिवारों को एन.डी.ए. के शासनकाल के दौरान कम ब्याज दरों पर लिए गए आवास ऋणों पर ई.एम.आई. (समान मासिक किस्तों) के रूप में बिना उनकी गलती के दोगुनी धनराशि अदा करनी पड़ रही है।

यू.पी.ए. सरकार द्वारा किसानों के लिए बढ़ा-चढ़ाकर की गई ऋण माफी की घोषणा मात्र एक प्रचार-हथकंडा है तथा यह भारतीय कृषि को पीड़ित करने वाली एक गंभीर और लम्बी बीमारी को ठीक करने की बेअसर दवा साबित हुई है।

यदि हम सत्ता में आए तो भाजपा और एन.डी.ए. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा को समाप्त करेगी। अर्थव्यवस्था में आ रही मंदी को उलटने के लिए हम तत्काल कदम उठाएंगे और वस्तुतः जी.डी.पी. की वृद्धि को दोहरे अंकों में ले जाएंगे। हालांकि जी.डी.पी. की अवधारणा को आम आदमी समझ नहीं पाता, इसलिए मैं चाहूंगा कि पार्टी **जी.डी.पी.** के बारे में हमारी विशिष्ट संकल्पना को लोगों को बताए—जिसमें **जी** यानी सभी स्तरों पर गुड़ गवर्नेंस (सुशासन), **डी** यानी सभी का डेवलपमेंट (विकास) और **पी** यानी प्रोटेक्शन(देश तथा आम आदमी की सुरक्षा)।

कश्मीर: 'विशेष दर्जे' से अलगाववाद की ओर

मित्रो, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से निपटते समय कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व ने ऐसी उदासीनता दिखाई है जिसे देखकर विगत के अनेक राष्ट्रवादी कांग्रेसियों को अवश्य धक्का लगा होगा। जरा सोचिए, भारत ने बंगलादेश की मुक्ति हेतु 1971 की लड़ाई में हासिल किए गए सभी सामरिक फायदों को किसी तरह से लगभग गंवा दिया है। बंगलादेश से बड़े पैमाने पर हो रही खतरनाक घुसपैठ के प्रति बाद की कांग्रेसी सरकारों की अपराधिक उदासीनता से आज भारत की एकता और असम तथा शेष पूर्वोत्तर की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आई.एम.डी.टी. एक्ट को असंवैधानिक बताकर रद्द करते हुए बंगलादेशियों की घुसपैठ को **"बाह्य आक्रमण"** की संज्ञा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह आई.एम.डी.टी. एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। यू.पी.ए. सरकार ने इस निर्देश की तिरस्कारपूर्वक अवहेलना की है। भला क्यों? **कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र वोट-बैंक नीति के कारण।**

जम्मू व कश्मीर की स्थिति को संभालने में नाकामयाब रही सरकार की जड़ में भी यही अल्पसंख्यकवाद से प्रभावित क्षुद्र नीति है— अमरनाथ श्राइन बोर्ड को किए गए भूमि आवंटन को रद्द करने हेतु अलगाववादियों के दबाव में आकर झुकना तथा बाद में जब श्रीनगर में अलगाव के नारे लगाए जा रहे थे, तो कायरता और भीरुता दिखाना। अमरनाथ मुद्दा न तो हिन्दू बनाम मुस्लिम था और न ही जम्मू बनाम कश्मीर था बल्कि यह राष्ट्रवादी बनाम अलगाववादी था। **हमारे पास जम्मू के लोगों के प्रति आभार जताने के लिए शब्द ही नहीं हैं क्योंकि उन्होंने केन्द्र की समझौतावादी सरकार को कम से कम अपनी पिछली गलती को आंशिक रूप से सुधारने हेतु मजबूर कर दिया।**

अमरनाथ के मुद्दे से एक बात स्पष्ट हो गई है : आज के कांग्रेस नेतृत्व ने मानसिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि कश्मीर शेष भारत से अलग है और उसे उसी तरह माना जाना चाहिए। “विशेष दर्जे से अलगाववाद” की ओर इस खतरनाक झुकाव को रोका जाना चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबन्धन की सहयोगी पार्टियां ही इसे रोक सकती हैं।

आतंक-विरोधी सख्त कार्रवाई हमारे 100 दिन के एजेण्डा का भाग रहेगा

सम्मानित साथियो, कल दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोटों— पिछले चार-पांच सालों में देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी हमलों की लम्बी श्रृंखला—से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी लड़ाई का एक नया चरण शुरू हो गया है। इसकी विशेष तथा विचलित करने वाली दो बातें हैं। पहली, यद्यपि इस लड़ाई के पीछे आतंकवाद के विश्वव्यापी नेटवर्क का हाथ रहा है, फिर भी **आतंकवाद की स्थानीय जड़ें व्यापक रूप में फैल चुकी हैं।** इसे राजनीतिक क्षेत्र के कुछ वर्गों से खुला समर्थन मिल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे देश में ऐसी सरकार है जो भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के दोषी व्यक्ति को दिए गए मृत्युदंड के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने से इंकार कर रही है। इस सरकार के दो कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक रूप से सिमी (simi) का पक्ष ले रहे हैं बगैर इस डर के कि उन्हें प्रधानमंत्री से कुछ सुनना पड़ सकता है।

ये दो खतरनाक लक्षण हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी को और अधिक बढ़ा दिया है। हमारी पार्टी प्राथमिक आवश्यकता की भावना से इस जिम्मेदारी को निभायेगी। यदि जनता नई दिल्ली में अगली सरकार बनाने के लिए हमें जनादेश देती है तो हम पोटा को दोबारा लायेंगे, राज्य-विशेष के आतंक विरोधी कानूनों को राष्ट्रपति से सहमति दिलाने की सिफारिश करेंगे तथा पहले सौ दिनों के भीतर अन्य सख्त उपचारी कदम उठायेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वाधिक वफादार समर्थकों से किस तरह बर्ताव किया!

मैं पहले कई बार कह चुका हूँ और फिर से दोहराना चाहता हूँ: यह हम नहीं, हमारे विरोधी हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को इस रूप में गलत व्याख्यायित कर रहे हैं कि यह इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध है। वे राष्ट्र और भारतीय मुस्लिम समुदाय — दोनों के लिए गलत रहे हैं। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम आतंकवाद को किसी मजहब या समुदाय के साथ जोड़ने के पूर्णतया विरोधी हैं। हम किसी भी समुदाय के निर्दोष लोगों के प्रति सशंकित या उत्पीड़न के विरुद्ध हैं।

मैं एक और अन्य उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे कांग्रेस पार्टी हमारे मुस्लिम बंधुओं के साथ अन्याय कर रही है। यूपीए सरकार सच्चर कमेटी के गठन को मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शा रही है। जबकि सत्य इसके विपरीत है – **सच्चर रिपोर्ट की एकमात्र विशेषता है कि इसने उजागर किया कि कांग्रेस पार्टी अब तक अपने सर्वाधिक वफादार समर्थकों के साथ किस तरह व्यवहार करती रही है।** क्या यह कांग्रेस नहीं है जिसने भारत पर सर्वाधिक लम्बे समय तक शासन किया है और भारतीय मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग की गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार नहीं है? और **यदि कांग्रेस अपने सर्वाधिक वफादार समर्थकों के साथ ऐसा बर्ताव करती रही है तो क्या इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह दूसरों से कैसा बर्ताव करेगी?**

हमारे मुस्लिम बंधुओं को हमारा विवेकपूर्ण तथा सीधा संदेश यह है कि हम बगैर किसी भेदभाव के भारत की विविधता भरे समाज के सभी वर्गों की समान चिंता करते हैं। हम प्रत्येक समुदाय से गरीबी और पिछड़ेपन को हटाने के लिए कटिबद्ध हैं। हालांकि हमारा यह विश्वास है कि इन समस्याओं का मजहब आधारित समाधान विभेदक और अप्रभावी है। **जरूरत है सुशासन और सुराजनीति सहित सर्वसमावेशी राष्ट्रीय दृष्टिकोण की।** सभी समुदायों के गरीब लोगों का राष्ट्र के विकास संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस दृष्टिकोण से समान विकास और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है।

भारतीय जनता पार्टी को तेलंगांना मुद्दे पर नेतृत्व करना होगा

मित्रो, यूपी.ए. सरकार के महा-धोखों पर बात करते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यूपी.ए. सरकार ने पिछले संसदीय चुनाव तथा 2004 के विधानसभा चुनावों के समय आन्ध्र की जनता से यह वायदा किया था कि उनकी सरकार एक अलग तेलंगांना राज्य बनाएगी। इसकी तुलना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार के ट्रेक रिकार्ड से करके देखें। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा याद रहेगा कि यह एन.डी.ए. सरकार ही थी जिसने ये तीन अलग राज्य बनाकर उनसे किए गए अपने वायदे को पूरा किया था।

तेलंगांना की अधिकांश जनता एक अलग राज्य चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने उनकी मांग के समर्थन में एक विशेष संकल्प पारित किया। एन.डी.ए. शासन के दौरान तेलुगुदेशम् पार्टी (टी.डी.पी) के साथ हमारे गठबंधन के कारण हम इस मामले में कार्रवाही नहीं कर सके। तथापि, अब स्थिति बदल चुकी है। आज बहुत ही कम राजनीतिक पार्टियां तेलंगांना राज्य का खुलकर विरोध करती हैं। इसलिए, अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से कुछ ऐसे ठोस कदम उठाकर इस मामले में नेतृत्व करे जिससे हम तेलंगांना की जनता के प्रिय बन सकें और इस क्षेत्र के लोगों से हमें इसी तरह व्यापक समर्थन मिलता रहे। मुझे

विश्वास है कि ऐसा करना हमारे लिए आगामी लोकसभा और आन्ध्रप्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी लाभप्रद सिद्ध होगा।

पार्टी के सम्मुख पांच कार्य

मेरे प्यारे सहयोगियो, मैंने पन्द्रहवीं लोकसभा के चुनावों की पृष्ठभूमि की कुछ बातों पर प्रकाश डाला है। जैसा मैंने कहा, एक असफल और बदनाम सरकार – स्वतंत्रता के पश्चात् नई दिल्ली की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार भी – ने अनेक कारण दिए हैं जिससे इसको हटाया जाए। लेकिन भाजपा भी अवश्य सब की पसंद बने। इसके लिए हमारे पार्टी संगठन को सभी स्तरों पर अनेक कार्य करने पड़ेंगे।

पहला, ऊपर से नीचे तक, पूरी पार्टी तुरन्त ही “अवश्य जीतने” के मूड में आनी चाहिए। इसके लिए विचारों में एकता, रणनीति में एकता और कदमों में एकता की जरूरत है।

दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में एनडीए को मजबूत करने और इसका विस्तार करने के लिए पहल करनी होगी। यह समय की आवश्यकता है। विशेषकर उन प्रदेशों में जहां भाजपा अभी भी एक मजबूत शक्ति के रूप में नहीं उभरी है। मजबूत सहयोगी पार्टियों के लिए एक सही मानसिकता की जरूरत है जो कभी-कभी नहीं दिखती। हम याद रखें कि आगामी लोक सभा चुनावों में भाजपा की अग्रसर भूमिका, हमारी सहयोगी बनाने की क्षमता की मजबूती पर निर्भर करेगी।

तीसरा, भारत में किसी अन्य पार्टी के पास ऐसे नेता नहीं हैं जिसके अनेक नेताओं की व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिभा और विशेषज्ञता की प्रशंसा होती हो। हमारे कार्यकर्ता और अधिकांश लोग टीम प्रयास देखना चाहते हैं, जो हमारे नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिभा के प्रभाव को बहुगुणित करेंगे। हमारा व्यवहार अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जैसा पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक हमसे अपेक्षा करते हैं।

यहां मैं स्पष्ट बता दूँ कि मैं कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शित रवैये से बहुत हताश होता हूँ जब वे बिना बारी के बोलने लगते हैं और भावी गठबन्धनों तथा हमारी चुनावी नीतियों के अन्य पहलुओं के बारे में सार्वजनिक तौर पर वक्तव्य देते हैं। क्या ऐसा किसी दूसरी पार्टी में होता है? इन बातों और अन्य नकारात्मक रवैयों से पार्टी के भीतर फूट पैदा होती है और ऐसी भावना को कड़ाई से रोका जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ही हमारी शक्ति है। इससे पंगु बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

चौथा, जनता उसी विपक्षी पार्टी में अपना विश्वास जताती है जो न केवल सरकार की विफलताओं पर ही प्रकाश डाले बल्कि यह दर्शाते हुए अपना निजी सकारात्मक एजेंडा भी प्रस्तुत करे कि वह उन मुद्दों को किस तरह से निपटाएगी जिनके बारे में वह सरकार की आलोचना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही सुशासन, विकास और सुरक्षा हेतु एक प्रेरक और व्यापक एजेंडा तैयार करेगी। मैं इस

प्रयास में देशभर के सभी बुद्धिजीवी लोगों से उनके विचार तथा सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

पांचवा, मुझे प्रसन्नता है कि पार्टी पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं, जो मतदाताओं में निर्णायक भूमिका निभाने वाला वर्ग है, तक पहुंचने के मुख्य काम में पहले से जुटी है। हमें इस गतिविधि को और तेज करना है। हमारा संदेश युवा भारतीयों के मन और दिमागों को जीतने का है। वे हमारे राष्ट्र के भविष्य को संवारेंगे और भाजपा के भविष्य को भी संवारेंगे।

मैं यहां पार्टी के सभी मोर्चों की अत्यधिक उपयोगी भूमिका का भी उल्लेख करना चाहूंगा। न केवल युवा मोर्चा ही बल्कि महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा भी मतदाताओं के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारे प्रकोष्ठों जैसे विधि प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, अध्यापक प्रकोष्ठ आदि को भी अधिक सक्रिय बनना होगा। पिछले महीनों में उनमें से कई मोर्चों और प्रकोष्ठों ने कुछ अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आने वाले दिनों में इन प्रयासों को और अधिक तेज करने तथा व्यापक बनाने की जरूरत है।

हमारे परिवार संगठनों द्वारा की गई कई उपयोगी पहलों की भी मैं सराहना करूंगा। हाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने के लिए दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से लेकर श्रीनगर में हजरत बल तक एक अद्वितीय पैगाम-ए-अमन यात्रा की।

मित्रो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे अपनी बात को समाप्त करूं। लेकिन ऐसा कुछ है, जो मैं आप सबसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस महत्वपूर्ण बैठक में, जब हम बड़े चुनावी संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, बांटना चाहता हूँ।

मैं श्री अटल जी की अनुपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। आज मैं उनके मार्गदर्शन और उनके साथ की कभी महसूस कर रहा हूँ। मैं कभी-कभी उस जिम्मेदारी, जो आपने मुझ पर डाली है, को निभाने में अकेला महसूस करता हूँ। मैं आपका समर्थन चाहता हूँ, आप सभी का सक्रिय और उत्साहपूर्ण सहयोग चाहता हूँ। एक ऐतिहासिक मिशन, जिसे पूरा करना आसान नहीं है, हमारा आह्वान कर रहा है। हम एकजुट रह कर फिर से जीत सकते हैं – और जीतेंगे—जैसे 1998 और 1999 में जीते थे।

धन्यवाद।

वन्देमातरम्